भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1860

4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईसीएमआर द्वारा अनुसंधान और नवाचार

1860. # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के बजट में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए आवंटन में पुनः वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कौन-कौन सी नई पहल की जा रही हैं; और

(ग) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैविकी (बायोलॉजिक्स) और दवाइयों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल देखरेख में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार ने अनुसंधान अनुदानों को और अधिक प्रतिस्पर्धी और सुलभ बनाने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान के बजट में वृद्धि के साथ-साथ नई योजनाएँ/पहल की हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के लिए बजटीय आवंटन के तहत 2024-25 के बजट अनुमान में ₹2,732.13 करोड़ से 2025-26 के बजट अनुमान में ₹3,125.50 करोड़ और 2026-27 के बजट अनुमान में ₹4,000.00 करोड़ तक वृद्धि हुई है। 2026-27 के लिए आवंटन 2025-26 के 3,150.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख): सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ बनाने के लिए भी उपाय किए हैं। आईसीएमआर ने सूचित किया है कि उसने अपने इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल अनुदान ढांचे को युक्तिसंगत और विस्तारित किया है ताकि वित्त पोषण सहायता का अनुसंधान प्रस्ताव के पैमाने, परिपक्वता, जोखिम और ट्रांसलेशनल स्टेज के अनुसार आकलन किया जा सके। आईसीएमआर ने प्रारंभिक अनुसंधान अनुदानों से प्राप्त लीड्स का उपयोग करने के लिए नए अनुवर्ती अनुदान शुरू किए हैं।

वर्तमान संरचना में 2 करोड़ रुपये तक का लघु या अन्वेषण अनुदान, 2 करोड़ रुपये से 8 करोड़ रुपये तक का मध्यवर्ती या निश्चायक अन्वेषण अनुदान, 8 करोड़ रुपये तक के चरण-आधारित समर्थन के साथ फर्स्ट-इन-द-वर्ल्ड चैलेंज और 15 करोड़ रुपये तक के समर्थन के साथ सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च शामिल हैं। ये उपकरण अन्वेषक द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान, अवधारणा-प्रमाण अध्ययनों, हस्तक्षेपों के सत्यापन, उच्च जोखिम और उच्च-प्रतिफल के नवाचार, बहु-विषयक अनुसंधान और उन्नत अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं।

आईसीएमआर ने यह भी सूचित किया है कि उसने सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए अनुसंधान बजट में वृद्धि करने और उसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक अनुसंधान वित्त पोषण अनुदान शुरू किए हैं।

i) शीर्ष स्तरीय वैश्विक नेतृत्व वित्त पोषण योजना: अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थाओं के रूप में शीर्ष दस एनआईआरएफ-रैंक वाले चिकित्सा संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख पहल।

ii) आईसीएमआर-राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) संयुक्त आह्वान: योग्यता-आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और मूल्यांकन सुधारों पर ध्यान देने के साथ चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों को बढ़ाने के लिए नवाचार और कार्यान्वयन अनुसंधान का समर्थन करने के लिए शीर्ष-100 एनआईआरएफ -रैंक वाले चिकित्सा संस्थानों द्वारा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और बढ़ाने के लिए अनुसंधान।

(iii) केन्द्र सरकार के तीन मेडिकल कॉलेजों, दिल्ली में आंतरिक अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए आईसीएमआर पहल।

iv) अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज (एमएएचए)-मेडिकल टेक्नोलॉजी (महा मेडटेक) शुरू किया है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाना, उच्च लागत वाले आयात पर निर्भरता कम करना और सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है।

v) आईसीएमआर क्लिनिकल केयर एक्सीलेंस इनिशिएटिव: गैर-संचारी रोगों का इलाज करने वाले बहु-केंद्र नैदानिक परीक्षण

(vi) व्यापक हितधारक परामर्शों के माध्यम से आईसीएमआर द्वारा पहचान की गई अपूर्ण नैदानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आईसीएमआर सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च (सीएआर) की स्थापना के लिए प्रस्तावों के लिए विशेष आह्वान। इस पहल का उद्देश्य मेडटेक क्षेत्र में व्यापक सार्वजनिक लाभ और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सस्ती, सुलभ और स्वदेशी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। टियर-1, टियर-2 और टियर-3 शहरों के चिकित्सकों सहित देश भर में विभिन्न नैदानिक स्थापनाओं में प्रख्यात चिकित्सकों को शामिल करते हुए एक कठोर अभ्यास के माध्यम से प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 100 प्राथमिकता वाली अपूर्ण नैदानिक आवश्यकता आधारित चिकित्सा उपकरण/नैदानिक प्रौद्योगिकियों की एक परिष्कृत सूची तैयार हुई है।

vii) भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत एक मापनीय उपशामक देखभाल मॉडल को विकसित करने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपशामक देखभाल हस्तक्षेपों के कवरेज में सुधार करने तथा मॉडल की लागत-प्रभावशीलता एवं व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने और उपशामक देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए साक्ष्य उत्पन्न करने हेतु आईसीएमआर का बहुराज्यीय कार्यान्वयन अनुसंधान अध्ययन।

(ग): आईसीएमआर पुनः संयोजक टीकों, जीवविज्ञान, सेल और जीन थेरेपी, रोबोटिक्स और एआई-टूल्स के विकास सहित अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए कई एक्स्ट्राम्यूरल (बाह्य) अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करता है। कैंसर के लिए सीएआर-टी सेल थेरेपी और रोबोटिक्स-आधारित लक्षित चिकित्सा, कार्डियक मालिश, रूट कैनाल उपचार सहित फ्रंटियर प्रौद्योगिकी की 22 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आईसीएमआर ने 97 चिकित्सा उपकरणों/नैदानिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास और 11 प्रौद्योगिकियों की लागत में कमी का समर्थन किया है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज में 60 से अधिक नवीन परियोजनाओं का समर्थन किया गया है।

घरेलू बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र को सुदृढ़ करने और बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत में सस्ती स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करने और भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास का समर्थन, नैदानिक परीक्षण बुनियादी ढांचे सुदृढीकरण और शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के माध्यम से यह योजना बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में घरेलू नवाचार और विनिर्माण क्षमताओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। इस तरह की पहल से समय के साथ आयात निर्भरता को कम करने और वैश्विक बायोफार्मास्युटिकल बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने में योगदान मिलने की उम्मीद है। दीर्घकालिक लक्ष्य नवाचार नेतृत्व की ओर बढ़ना है, जिसमें एआई-डिज़ाइन किए गए जीवविज्ञान और उन्नत उपचार और सटीक चिकित्सा शामिल हैं ताकि इन्हें अधिक किफायती और सुलभ बनाया जा सके।

*****